काली मिर्च के निर्यात पर शुल्क लगाया जाना

1675. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने काली मिर्च के निर्यात पर भारी शुल्क लगा दिया है जिसके कारण काली मिर्च के निर्यात पर प्रभाव पड़ा है तथा उसकी कीमत में भी भारी गिरावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने काली मिर्च के निर्यात पर कितना शुल्क लगाया है ; और

(ग) क्या सरकार काली मिर्च को निर्यात शुल्क से मुक्त करने का विचार रखती है ताकि इसका निर्यात अपने पूर्व स्तर पर पहुंच जाये तथा उससे सरकार को भी विदेशी मुद्रा मिले ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० आर० दासमुंशी) : (क) से (ग) पहले काली मिर्च के निर्यात पर 5,000 रुपए प्रति मी०टन की दर से निर्यात शुल्क लगाया जाता था, परन्तु 20 सितम्बर, 1988 से काली मिर्च को निर्यात शुल्क से छूट दे दी गई है ।

Bank credit for industrial development in Madhya Pradesh

1676. SHRI AJIT P. K. JOGI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the total Bank credit made available to Madhya Pradesh for industrial development during the last three years;

(b) what was the corresponding figure for Maharashtra, Uttar Pradesh and Tamil Nadu; and

(c) what steps are being taken to augment it for a backward state like Madhya Pradesh?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) to (c) The outstanding advances of scheduled commercial banks to Industry in Madhya Pradesh, Maharashtra, Uttar Pradesh and Tamil Nadu as at the end of December 1984, December 1985 and December 1986 are given below:-

(Amount in Rs. crores)

States	(Outstanding advances to Industry)		
	1984	1985*	1986*
Madhya Pradesh	563.15	681.75	867.16
Maharashtra	4661 00	6094 84	8177.28
Tamil Nadu	1815.01	2425.50	2997.30
Uttar Pradesh	1159 06	1465 09	1857.99

*Data are provisional.

Banks have been advised by the Reserve Bank of India (RBI) to ensure that wide disparities among various States in credit deployment are avoided and to take effective steps to increase the flow of credit to deficient areas. The Policies are aimed at removing the regional imbalances in banking infrastructure and flow of credit.